

भारत राज्य व अन्य

बनाम

मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 8621/2010)

06 मई 2014

[अनिल आर. दवे और ए.के. सीकरी, जे.जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944:

आर.57 सीसी आर/ आरआर.57 ए, 57 बी और 57 डी-मॉडवेटल का समायोजन छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में प्रयुक्त इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट और द्वारा अलग-अलग इन्वेंट्री और इनपुट के खातों का रखरखाव निर्माता-सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, ट्राइक्लोरो एथिलीन, फॉस्फोरिल ए और फॉस्फोरिल बी, द्वारा साफ किया गया उर्वरक संयंत्रों के लिए निर्धारितियों द्वारा निष्पादित बांड के संदर्भ में उत्तरार्द्ध-आयोजित: तकनीकी रूप से, व्यावसायिक रूप से और सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में, सल्फ्यूरिक एसिड को उप-उत्पाद के रूप में माना जाता है न केवल कंपनियों द्वारा अलौह धातुओं का निष्कर्षण भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कास्टिक सोडा से जुड़े तथ्य, ट्राइक्लोरो एथिलीन, फॉस्फोरिल ए और फॉस्फोरिल बी हैं समान-इसमें कोई संदेह नहीं है, आर.57 सीसी के लिए एक निर्धारिती की

आवश्यकता है। इसमें उपयोग किए जाने वाले इनपुट के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखें दो या दो से अधिक अंतिम उत्पादों का निर्माण जिनमें से एक है। शुल्कयोग्य और दूसरा गैर-शुल्कयोग्य है-लेकिन के मामले में उत्तरदाताओं, जिंक सांद्रण की पूरी मात्रा है। वास्तव में जस्ता के उत्पादन में उपयोग किया गया है और कोई भी भाग नहीं हो सकता है।

सल्फ्यूरिक एसिड में पाया जा सकता है-यह इस कारण से है, उत्तरदाताओं ने जिंक सांद्रण की सूची बनाए रखी जस्ता का उत्पादन और, इसलिए, कोई आवश्यकता नहीं थी और वास्तव में, इसके लिए अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखना असंभव है। सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला जिंक सांद्रण इसलिए, उच्च न्यायालय ने इन आवश्यकताओं को सही ठहराया है। आर.57 सीसी उत्तरदाताओं के तरीके से पूरी तरह से संतुष्ट थे जिस तरीके से रिकॉर्ड और सूची बनाए गये और जो गलत तरीके से रूल 57 सीसी के तहत छुट प्राप्त सल्फ्यूरिक एसिड पर 8% की रिकवरी की गई है, इस संबंध में लागू नहीं है। अधिसूचना संख्या 6/2002-सीई।

भारत का संविधान, 1950:

कला 226-वैकल्पिक उपाय एवं रिट की पोषणीयता याचिका कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई। आर के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जारी किया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नियम की धारा 57 सीसी माना गया: यह केवल कारण बताओ नोटिस की वैधता नहीं थी। सवाल किया गया-रिट याचिका में भी आर की शक्तियाँ। 57 सीसी चुनौती दी गई-यही एक कारण था जिसकी वजह से रिट याचिकाओं पर विचार किया गया, और यह सही भी है, यह एक अलग बात है। मामला यह है कि नियम की व्याख्या करते समय हाई कोर्ट ने चुना। उक्त नियम को पढ़ना और उसकी व्याख्या करना। इसे असंवैधानिकता के दोष से बचाएगा-केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944-रूल. 57 सीसी.

राजस्व द्वारा दायर तत्काल अपीलें सामने आईं, उच्च न्यायालय और ट्रिब्यूनल के निर्णयों के बारे में उत्तरदाताओं-निर्धारिती के दावे को अनुमति देते हुए। वे इनपुट पर मॉडवैट/सेनवेट क्रेडिट के हकदार थे। का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा फ्लेक्स, के उत्पादन में किया जाता है। ट्राइक्लोरो एथिलीन, फॉस्फोरी/ए और फॉस्फोरिल बी जो उन्होंने शर्तों में छूट के तहत उर्वरक संयंत्रों को मंजूरी दे दी। उर्वरक संयंत्रों द्वारा निष्पादित बांडों के संदर्भ में अधिसूचना संख्या 6/2002-सीई.

न्यायालय के समक्ष विचार हेतु प्रश्न थे: उत्तरदाताओं की पात्रता के संबंध में/इनपुट के उपयोग के लिए निर्धारितियों को मॉडवैट/सेनवेट क्रेडिट आरएन. अंतिम उत्पादों का निर्माण जो छूट प्राप्त हैं या शुल्क की शून्य दर के अधीन; और की आवश्यकता निर्धारिती के संबंध में अलग खाते बनाए रखने के लिए शुल्क योग्य वस्तुओं के साथ-साथ छूट प्राप्त वस्तुओं में

उपयोग किए जाने वाले इनपुट और निर्धारिती की विफलता पर उत्पन्न होने वाला दायित्व ऐसे अलग खाते बनाए रखें।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित: 1.1. सीए नंबर 8621-8630/2010 ए में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी अपने सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र में उत्पादित सल्फ्यूरिक एसिड के हिस्से और इफको को बेचे जाने वाले स्मेल्टर में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए शुल्क पर मॉडवैट क्रेडिट का लाभ उठाना चाहता है। उर्वरक का एक निर्माता, जो समय-समय पर जारी छूट अधिसूचनाओं के संदर्भ में कर्तव्यों के भुगतान पर उर्वरकों के निर्माण में इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले सल्फ्यूरिक एसिड को प्राप्त करने की रियायत का लाभ उठाने का हकदार है। जहां तक सल्फ्यूरिक एसिड का सवाल है, अंतिम उत्पाद के रूप में यह टैरिफ हेड 28 के तहत शुल्क योग्य है। टैरिफ अधिनियम के तहत प्रदान की गई शुल्क की दर 16% यथामूल्य है। हटाए जाने पर सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण पर शुल्क के भुगतान से निर्माता को कोई छूट नहीं है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 ए की उप-धारा 1 के तहत जारी सामान्य छूट संख्या 66 के तहत केंद्र सरकार ने उक्त छूट आदेश से जुड़ी तालिका के (3) में निर्दिष्ट विवरण के उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को छूट दी है। जहां तक सल्फ्यूरिक एसिड का संबंध है, जिसका उपयोग उर्वरकों के निर्माण में

किया जाता है, शून्य शुल्क प्रदान किया जाता है। हालाँकि, तालिका इंगित करती है कि यह शर्त संख्या 5 के अधीन है। शर्त संख्या 5 का उल्लेख सामान्य छूट संख्या 66 से जुड़े अनुबंध में किया गया है। [पैरा 10-11] [299-जी-एच; 300-ए-सी]

1.2. सल्फ्यूरिक एसिड वास्तव में एक उप-उत्पाद है। वास्तव में, उत्तरदाताओं द्वारा अपनी बैलेंस शीट के साथ-साथ विभिन्न अन्य दस्तावेजों में भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है, जो उत्तरदाताओं द्वारा नीचे की अदालतों में दायर किए गए थे। यह भी पार्टियों का एक सामान्य मामला है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और बिड़ला कॉपर की स्थापना क्रमशः जस्ता और तांबे का उत्पादन करने के लिए की गई थी, न कि सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था, जिसे विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा विवादित नहीं किया जा सकता था, कि केंद्रित अयस्क की कैल्सीनेशन प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड का उद्भव एक तकनीकी आवश्यकता है और फिर गैर के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड में इसका रूपांतरण होता है। -प्रदूषणकारी उपाय सल्फ्यूरिक एसिड को अंतिम उत्पाद की स्थिति तक नहीं बढ़ा सकते। तकनीकी रूप से, व्यावसायिक रूप से और आम बोलचाल में, सल्फ्यूरिक एसिड को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर की कंपनियों द्वारा अलौह धातुओं के निष्कर्षण में एक उप-उत्पाद के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि विभाग ने ट्रिब्यूनल के समक्ष यह स्थिति स्वीकार कर ली कि

सल्फ्यूरिक एसिड एक उप-उत्पाद है। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता द्वारा अब ली गई स्थिति कि सल्फ्यूरिक एसिड को उप-उत्पाद के रूप में नहीं माना जा सकता है, को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 16-17]  
[304-8-एफ]

2.1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का नियम 57 सीसी इसके लिए निर्धारिती को अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे इनपुट जिनका उपयोग दो या दो से अधिक के निर्माण में किया जाता है

सी अंतिम उत्पाद जिनमें से एक शुल्क योग्य है और दूसरा शुल्क योग्य है। शुल्क देय नहीं। उस स्थिति में, आर.57 सीसी लागू होगा। लेकिन जब हम पाते हैं कि उत्तरदाताओं के मामले में, ऐसा नहीं है कि जिंक अयस्क सांद्रण की कुछ मात्रा सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में चली गई है, तो नियम 57 सीसी की प्रयोज्यता को आकर्षित किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिंक की पूरी मात्रा वास्तव में जिंक के उत्पादन में उपयोग की गई है और सल्फ्यूरिक एसिड में इसका कोई हिस्सा नहीं पाया जा सकता है। यही कारण है कि, उत्तरदाताओं ने जिंक के उत्पादन के लिए जिंक सांद्रण की सूची बनाए रखी और हम उत्तरदाताओं के इस कथन से सहमत हैं कि उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले जिंक

सांद्रण के लिए अलग रिकॉर्ड बनाए रखना कोई आवश्यकता नहीं थी और वास्तव में यह असंभव है। [पैरा 20-] [305-डी-एच; 306-ए]

2.2. इसलिए, उच्च न्यायालय ने इसे सही ठहराया है। रास्ते में आर.57 सीसी की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया गया। जिसका उत्तरदाता रिकॉर्ड रख रहे थे और इन्वेंट्री और आर.57 के तहत 8% की वसूली की शरारत छूट प्राप्त सल्फ्यूरिक एसिड पर सीसी आकर्षित नहीं होता है। [पैरा 20] जी [306-8]

2.3. बिड़ला कॉपर (2011 के सी.ए. नं. 2337) के मामले में तांबे के अयस्क सांद्रण से तांबे की विनिर्माण प्रक्रिया जस्ता के समान है और उप-उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड के उद्भव को विभाग द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष स्वीकार किया गया था। यहां भी, बिड़ला कॉपर शुल्क के भुगतान पर विभिन्न उद्योगों को उप-उत्पाद सल्फ्यूरिक एसिड बेच रहा था और उर्वरक संयंत्रों द्वारा निष्पादित बांड के आधार पर उर्वरक संयंत्र को शुल्क का भुगतान किए बिना सल्फ्यूरिक एसिड को साफ कर रहा था। ट्रिब्यूनल ने मामले का फैसला करदाता के पक्ष में सुनाया है। स्वदेशी लिमिटेड के मामले में फैसले के बाद। कास्टिक सोडा फ्लेक्स के संबंध में अन्य अपीलों में तथ्य, ट्राइक्लोरो एथिलीन, फॉस्फोरिल ए और फॉस्फोरिल बी तथ्यों और निर्धारित कानून के समान प्रतीत होते हैं। स्वदेशी पॉलीटेक्स में. इसलिए, यह निर्णय बिल्कुल सही है। [पैरा 4,22 और 25) [306-ए-सी; 308-ई]

स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड बनाम सीसीई; 1989 (44) ईएलटी 794-विश्वसनीय पर।

2.4. इसके अलावा, नियम 57 सीसी के प्रावधानों को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इस नियम में निहित मोडवैट क्रेडिट की योजना को समझने के लिए, नियम 57 ए, 57 बी और 57 डी के साथ-साथ नियम 57 सीसी को एक साथ पढ़ना अपरिहार्य हो जाता है। हमने पहले ही ऊपर नियम 57 डी पुनः प्रस्तुत कर दिया है। उपरोक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह आसानी से समझा जा सकता है कि इस्तेमाल किए गए शब्द 'इनपुट', 'अंतिम उत्पाद', 'उप-उत्पाद', 'अपशिष्ट उत्पाद' आदि हैं। हमारा मानन है कि इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। व्यापार में व्यावसायिक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए। उस संदर्भ में जब हम नियम 57 सीसी के माध्यम से स्कैन करते हैं, तो समान सामान्य इनपुट के साथ निर्मित अंतिम उत्पाद का संदर्भ समझ में आता है। [पैरा 26) [308-एफ-एच; 309-ए)

सीसीई बनाम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड; 2008 (232) ईएलटी 7 -विश्वसनीय पर।

3. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका के वैकल्पिक उपचार और गैर-सुनवाई योग्य होने की दलील के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष सीमित, हालांकि इसे शो जी में दायर किया गया था। कारण



बताओ चरण, यह केवल कारण बताओ की वैधता नहीं थी। नोटिस जिस पर सवाल उठाया गया था. रिट याचिका में भी आर के वायर्स 57 सीसी को चुनौती दी गई। यही एक कारण था जिसके कारण रिट याचिकाओं पर विचार किया गया, और यह सही भी है, यह अलग बात है कि नियम की व्याख्या करते समय, उच्च न्यायालय ने उक्त नियम को पढ़ने और एक व्याख्या देने का फैसला किया जो इसे बुराई से बचाएगा। असंवैधानिकता का. इसके अलावा, विभाग द्वारा दायर की गई अन्य वैधानिक अपील सीईएसटीएटी के आदेश के खिलाफ है, जिसमें समान प्रश्न शामिल है।  
[पैरा 28] [309-एफ-एच]

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड बनाम सीसीई 2005 (191) ईएलटी 401; बिनानी जिक लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोचीन 2005 (187) ई.एल.टी. 390 (त्रि.-बेंग.); और रैलिस इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ; 2009 (233) ईएलटी 301-उद्धृत।

#### केस कानून संदर्भ:

2005 (191) ईएलटी 401	उद्धृत	पैरा 4
2005 (187) ई.एल.टी. 390		
(टाई-बेंग।)	उद्धृत	पैरा 6
1989 (44) ईएलटी 794	विश्वसनीय	पैरा 24
2008 (232) ईएलटी 7	विश्वसनीय	पैरा 24

2009 (233) ईएलटी 301 उद्धृत

पैरा 24

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8621/2010

राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट याचिका संख्या 6776/2005 की 23.01.2007 के निर्णय एवं आदेश से

साथ

2012 की सिविल अपील संख्या 1181

2011 की सिविल अपील संख्या 2337

सिविल अपील संख्या 5322, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 2010 का 8628, 8629, 8630 और 8631।

के. स्वामी, सुनीता रानी सिंह, सुनीता राव, बी.के. प्रसाद, बी.वी. बलराम दास, अनिल कटियार, बी. कृष्णा प्रसाद, अरविंद अपीलकर्ताओं की ओर से कुमार शर्मा।

एस.के. बागरिया, आलोक यादव, प्रवीण कुमार, सुनैना कुमार, एम.पी. देवनाथ, मनीष बिश्रोई, अभय ए जेना, अनुज धीर, रंजीत राऊत, बीना गुप्ता, नितीश मैसी, संजीव के. कपूर प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एके सीकरी, जे.

1. ये सभी अपीलें कानून के समान प्रश्न उठाती हैं, जो लगभग समान परिस्थितियों में उत्पन्न हुई हैं। वास्तव में, इसमें शामिल मुद्दे का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच में किया गया था। हिंदुस्तान जिंक ने दिनांक 23.1.2007 के फैसले के तहत संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एसएलपी दायर की थी जिसमें अनुमति दे दी गई है। अन्य मामले में, वही मुद्दा सी ESTAT द्वारा तय किया जाता है जिसके खिलाफ वैधानिक अपील चुनी जाती है। यही कारण है कि इन सभी अपीलों को एक साथ एकत्रित किया गया और सामूहिक रूप से सुनवाई की गई।

2. शुरुआत में, इसमें शामिल विवाद को यह इंगित करके प्रतिबिंबित किया जा सकता है कि विचार के लिए प्रश्न अंतिम उत्पादों के निर्माण में इनपुट के उपयोग के लिए मॉडवैट/सेनवेट क्रेडिट के लिए उत्तरदाताओं/निर्धारिती की पात्रता से संबंधित हैं, जो छूट प्राप्त हैं या शुल्क की शून्य दर और शुल्क योग्य वस्तुओं के साथ-साथ छूट प्राप्त वस्तुओं में उपयोग किए गए इनपुट के संबंध में अलग खाते बनाए रखने के लिए निर्धारिती की आवश्यकता और ऐसे अलग खातों को बनाए रखने में निर्धारिती की विफलता पर उत्पन्न होने वाली देयता के अधीन। 2010 की सिविल अपील संख्या 8621-8630 में, हम सल्फ्यूरिक एसिड से चिंतित हैं। 2010 की सिविल अपील संख्या 8631 में, यह कास्टिक सोडा फ्लेक्स और ट्राइक्लोरो एथिलीन है। 2011 की सिविल अपील संख्या 2337 में, उत्पाद फिर से

सल्फ्यूरिक एसिड है और 2010 की सिविल अपील संख्या 5322 और मेसर्स रैलिस इंडिया लिमिटेड के अन्य संबंधित मामले में, यह फॉस्फोरिल ए और फॉस्फोरिल बी है। मुद्दा यह इस बात से संबंधित है कि क्या निर्धारिती (प्रतिवादी) उपरोक्त छूट प्राप्त (या शुल्क की शून्य दर के अधीन) अंतिम उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए गए इनपुट पर मॉडवैट/सेनवेट क्रेडिट के हकदार हैं।

3. राजस्व द्वारा दायर इन सभी अपीलों में, इसने आम विवाद के साथ स्थिति ले ली है कि क्या प्रतिवादी केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 या 57AD के नियम 57 सीसी के तहत राशि के रूप में 8% उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2000 या सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) उप-उत्पाद अर्थात् सल्फ्यूरिक एसिड के मूल्य पर, जिसे उर्वरक संयंत्रों को निष्पादित बांड के संदर्भ में छूट के तहत मंजूरी दे दी गई थी। उर्वरक संयंत्र.

4. इस स्तर पर हम तीनों मामलों में विनिर्माण प्रक्रिया और वर्तमान अपील दायर करने से जुड़े तथ्यों का वर्णन करेंगे।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (सीए नंबर 8621-8630/2010)

i) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने उत्पाद शुल्क के भुगतान पर खदानों से जिंक अयस्क सांद्रण प्राप्त किया, जिसका उपयोग जिंक के उत्पादन के

लिए इनपुट के रूप में किया जाता है। जिंक अयस्क मुख्य रूप से जिंक सल्फाइड (ZnS) के रूप में उपलब्ध है।

ii) जब ZnS को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म (कैल्सीनीकृत) किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड (ZnO) और सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होते हैं। जिंक ऑक्साइड को जिंक उत्पन्न करने के लिए आगे ऑक्सीकरण किया जाता है। तकनीकी आवश्यकता के रूप में प्राप्त सल्फर एक प्रदूषक है और इसलिए, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर में बदल दिया जाता है और प्रतिवादी सल्फर डाइऑक्साइड के उद्भव के बाद उपयोग किए गए इनपुट पर कोई सेनवैट क्रेडिट नहीं लेता है। उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित सल्फ्यूरिक एसिड विभिन्न उद्योगों को उत्पाद शुल्क के भुगतान पर बेचा जाता है। उत्पाद शुल्क अधिकारियों की संतुष्टि के लिए उर्वरक संयंत्रों द्वारा बांड के निष्पादन पर अधिसूचना संख्या 6/2002-सीई के अनुसार सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ मात्रा उर्वरक संयंत्रों को बेची जाती है। उक्त सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जिंक के उत्पादन के लिए किया जाता है।

iii) उत्पाद शुल्क विभाग ने यह विचार किया कि नियमों के नियम 57 सीसी के संदर्भ में, उत्तरदाताओं को जस्ता और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट के लिए अलग-अलग खाते और

रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए बाध्य किया गया था और इसके अभाव में उत्तरदाताओं को नियम 57 सीसी के संदर्भ में उर्वरक संयंत्रों को सल्फ्यूरिक एसिड की बिक्री मूल्य पर 8% राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य थे। प्रतिवादी ने यह तर्क देकर अधिक बचाव किया कि सल्फ्यूरिक एसिड को छूट देने का उद्देश्य प्रासंगिक अवधि के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के लिए इनपुट लागत को सबसे कम रखना था। उर्वरकों को उत्पाद शुल्क के भुगतान से पूरी तरह छूट दी गई थी क्योंकि सरकार चाहती थी कि किसान को खेत की कीमत सबसे कम होनी चाहिए। दरअसल, सरकार उर्वरक संयंत्रों को उत्पादन लागत और सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य के बीच के अंतर के लिए सब्सिडी देती है। यह उनका बचाव था कि सल्फ्यूरिक एसिड पर किसी भी शुल्क की मांग छूट देने के मूल उद्देश्य को विफल कर देगी और उर्वरक की लागत वांछनीय स्तर से अधिक हो जाएगी। ऐसे में इतनी अधिक लागत की भरपाई सरकार को सब्सिडी के तौर पर करनी होगी.

iv) प्रतिवादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी, मुख्य रूप से नियम 57 सीसी की शक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी कि केंद्र सरकार अधीनस्थ कानून द्वारा कर्तव्यों की दरें तय नहीं कर सकती है जो कि विशेषाधिकार है केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के तहत संसद में केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 के

साथ पठित किया गया। नियम 57 सीसी की शक्तियों के संबंध में अन्य तर्क भी उठाए गए। एक विकल्प के रूप में, यह दलील दी गई कि भले ही नियम 57 सीसी को अधिकारातीत माना जाए, कारण बताओ नोटिस में उठाई गई मांग नियमों के नियम 57 सीसी की उचित व्याख्या पर टिक नहीं पाएगी और इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने अधिकारों से संबंधित प्रश्न पर गौर किए बिना, नियम 57 सीसी और नियम 57 डी की व्याख्या पर ही याचिका का फैसला उत्तरदाताओं के पक्ष में कर दिया। विभाग इस फैसले के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष अपील में है।

बिड़ला कॉपर (सीए नं. 2337/2011)

i) तांबे के अयस्क सांद्रण से तांबे की विनिर्माण प्रक्रिया जस्ता के समान है और उप-उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड के उद्भव को विभाग द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष स्वीकार किया गया था। यहां भी, बिड़ला कॉपर शुल्क के भुगतान पर विभिन्न उद्योगों को उप-उत्पाद सल्फ्यूरिक एसिड बेच रहा था और उर्वरक संयंत्रों द्वारा निष्पादित बांड के आधार पर उर्वरक संयंत्र को शुल्क का भुगतान किए बिना सल्फ्यूरिक एसिड को साफ कर रहा था। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड बनाम सीसीई के 2005 (191) ईएलटी 401 के मामले में अपने फैसले के बाद प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। उस मामले में स्टरलाइट तांबे

और ए का निर्माता भी था। उसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बिडला कॉपर के प्रतिस्पर्धी और ट्रिब्यूनल ने माना कि स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड बनाम सीसीई के 1989 के मामले में इस अदालत के फैसले के मद्देनजर उर्वरक संयंत्रों को दिए गए सल्फ्यूरिक एसिड पर 57 सीसी के तहत उत्पाद शुल्क देय नहीं था। 44) ईएलटी 794। ट्रिब्यूनल ने स्टरलाइट (सुप्रा) के मामले में भी माना कि 57 सीसी केवल तभी लागू होगा जब दो या दो से अधिक अंतिम उत्पादों के निर्माण में समान इनपुट का उपयोग किया जा रहा हो, जिनमें से एक को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है और निर्धारिती अलग खाता और अलग सूची नहीं बना रहा था। इस मामले में, ट्रिब्यूनल ने माना कि सल्फ्यूरिक एसिड अंतिम उत्पाद नहीं था, बल्कि केवल एक उप-उत्पाद था और इसलिए नियम 57 सीसी लागू नहीं होगा, खासकर जब हम इसे नियम 57 डी के आलोक में पढ़ते हैं। विभाग की अपील ट्रिब्यूनल के इसी आदेश के खिलाफ है। गौरतलब है कि विभाग ने उप-उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड के उद्भव पर विवाद नहीं किया है। हमें यह भी सूचित किया गया है कि विभाग ने स्टरलाइट (सुप्रा) के निर्णय को चुनौती देते हुए कोई अपील दायर नहीं की है और इसे विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान अपील में, विभाग का तर्क यह है कि स्टरलाइट (सुप्रा) 1.4.2000 से पहले की अवधि के लिए लागू होगा जब नियम 57 डी लागू था और 1.4.2000 के बाद नियम हटा दिया गया था।



रैलिस इंडिया लिमिटेड (सीए नंबर 5322/2010)

i) रैलिस इंडिया कैप्सूल के निर्माण के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग में उपयोग के लिए जिलेटिन के निर्माण में लगी हुई है। जिलेटिन का उत्पादन गोजातीय जानवरों की हड्डियों के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रिया से होता है। प्रतिक्रिया के दौरान, हड्डी ओसीन में परिवर्तित हो जाती है जिसका उपयोग जिलेटिन के उत्पादन के लिए किया जाता है। फॉस्फोरस आदि अकार्बनिक पदार्थों को पानी से धोया जाता है जिसे मातृ मदिरा, प्रयुक्त मदिरा या फॉस्फोरल मदिरा कहा जाता है जब इन उप-उत्पादों और अपशिष्ट उत्पादों को शुल्क के भुगतान के बिना साफ़ किया जाता है, तो उत्पाद शुल्क विभाग ने नियम 57 सीसी के संदर्भ में 8% की दर से शुल्क की मांग की। यहां भी, क्या मूल शराब एक अपशिष्ट उत्पाद है या उप-उत्पाद है, इस पर विभाग द्वारा ट्रिब्यूनल या बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद नहीं किया गया था। ट्रिब्यूनल ने नियम 57 सीसी की व्याख्या करके निर्धारिती के खिलाफ मामले का फैसला किया। इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने ट्रिब्यूनल के फैसले को पलट दिया है। विभाग उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील में है।

उपरोक्त कथन अपीलों के तीन सेटों में मुद्दे की पहचान का खुलासा करता है। अब से, हमारी चर्चा में, प्रतिवादी के रूप में, हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड का संदर्भ होगा।

5. यहां प्रतिवादी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका विनिवेश अप्रैल, 2002 में किया गया था। प्रतिवादी जस्ता, सीसा और साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट जैसी अलौह धातुओं के निर्माण में लगा हुआ है। उक्त उत्पाद उनके अन्य उत्पादों के बीच क्रमशः केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय उप-शीर्ष संख्या 2807.00, 7901.10 और 2833.10 के तहत प्रभार्य हैं। रुपये की वसूली के लिए निर्धारित प्रतिवादी को 15.3.2005 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 48,39,883/- पूर्ववर्ती सेनवैट क्रेडिट नियम, 2002 के नियम 12 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11(ई) के साथ पठित सेनवैट क्रेडिट नियम 2004 के नियम 14 के तहत ब्याज और दंड प्रावधानों के साथ।

6. प्रतिवादी ने सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 की संवैधानिक वैधता के साथ-साथ दिनांक 15.3.2005 के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष रिट याचिका संख्या 6776/2005 दायर की। प्रतिवादी ने उक्त रिट याचिका में प्रस्तुत किया कि जिंक और सीसा के निर्माण के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है और पर्यावरण नियंत्रण आवश्यकताओं के कारण, उन्हें इसे हवा में जारी करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इसलिए, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए किया जाता है, जो जस्ता और सीसा जैसी अलौह धातुओं के निर्माण के लिए इनपुट है,

इसे सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए सामान्य इनपुट के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि सल्फर ही एकमात्र घटक है जो सांद्रण में जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में। इसके अलावा, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि सेनवैट क्रेडिट नियमों का नियम 6 केंद्र सरकार की शक्ति से परे है और इसलिए अधिनियम के प्रावधानों से परे है। पूर्ववर्ती मॉडवैट क्रेडिट नियमों के नियम 57 सीसी की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई थी। यह कहा गया था कि ट्रिब्यूनल ने बिनानी जिंक लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोचीन-2005 (187) ईएलटी 390 (त्रि.-बंग.) के मामले में फैसले में माना है कि नियम 57 सीसी के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। अंतिम उत्पाद को छूट दी गई है और उप-उत्पाद को छूट दी गई है और इसलिए, ट्रिब्यूनल के पास जाने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

7. अपीलकर्ता ने जवाबी हलफनामे के माध्यम से उक्त रिट याचिका का विरोध किया जिसमें अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-निर्धारिती अंतिम उत्पाद यानी सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के संबंध में इनपुट की प्राप्ति और उपयोग के लिए अलग सूची और खाता नहीं रख रहा था। नियमों के नियम 6(2) के प्रावधानों के अनुसार शुल्क की शून्य दर। यदि शुल्क योग्य अंतिम उत्पाद और छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण के लिए सामान्य इनपुट का उपयोग किया जाता है तो नियमों के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। यह भी तर्क दिया गया कि यह स्वीकार किए

बिना कि सल्फ्यूरिक एसिड उप-उत्पाद है, छूट प्राप्त वस्तुओं के मूल्य के 8% के बराबर राशि को उलटना अनिवार्य था क्योंकि नियमों के नियम 6 के प्रावधानों में प्रयुक्त शब्द "छूट वाली वस्तुएं हैं" और अंतिम उत्पाद को छूट नहीं दी गई है" , यह दलील दी गई कि रिट याचिका समय से पहले है और निर्धारिती ने कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया है।

8. उच्च न्यायालय विनिर्माण प्रक्रिया के साथ-साथ नियम की स्थिति की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि छूट प्राप्त वस्तुओं पर या शुल्क की शून्य दर के अधीन मॉडवैट क्रेडिट का दावा करने पर प्रतिबंध उस मामले में लागू होता है, जहां शुल्क के भुगतान या शून्य दर से ऐसी छूट होती है। अंतिम उत्पाद पर शुल्क अनुमानित रूप से उस समय ज्ञात होता है जब इनपुट प्राप्तकर्ता ऐसे इनपुट पर भुगतान किए गए शुल्क का क्रेडिट लेने का हकदार होता है। तथ्य यह है कि बाद की अधिसूचना के कारण या भविष्य में उत्पन्न होने वाली आकस्मिकता पर, अंतिम उत्पाद को छूट या शुल्क की शून्य दर के कारण शुल्क के भुगतान के बिना मंजूरी दे दी जाती है, जो पात्रता की तारीख पर मॉडवैट क्रेडिट का लाभ उठाने को प्रभावित नहीं करता है। यदि पात्रता की तिथि पर, ऐसे मॉडवैट/सेनवैट क्रेडिट का क्रेडिट लेने में कोई अवैधता या अमान्यता नहीं है, तो शुल्क के प्रति भविष्य की देनदारी के खिलाफ ऐसे क्रेडिट का

उपयोग करने का अधिकार अपरिहार्य हो जाता है और ऊपर चर्चा की गई आकस्मिकता में उलटा होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

9. इन निष्कर्षों पर, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-हिंदुस्तान जिंक द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दे दी है। इस प्रक्रिया में उसमें निहित योजना की व्याख्या करने वाले प्रासंगिक नियमों की विस्तृत चर्चा होती है; केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 57 सीसी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2000 के 57 एडी और सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 के तहत 8% उत्पाद शुल्क के भुगतान के पहलू पर।

10. उपरोक्त कथन से, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी अपने सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र में उत्पादित सल्फ्यूरिक एसिड के हिस्से और इफको को बेचे जाने वाले स्मेल्टर में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए शुल्क पर मॉडवैट क्रेडिट का लाभ उठाना चाहता है। उर्वरक का एक निर्माता, जो समय-समय पर जारी छूट अधिसूचनाओं के संदर्भ में कर्तव्यों के भुगतान पर उर्वरकों के निर्माण में इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले सल्फ्यूरिक एसिड को प्राप्त करने की रियायत का लाभ उठाने का हकदार है। जहां तक सल्फ्यूरिक एसिड का सवाल है, अंतिम उत्पाद के रूप में यह टैरिफ हेड 28 के तहत शुल्क योग्य है। टैरिफ अधिनियम के तहत प्रदान की गई शुल्क की दर 16% यथामूल्य है। हटाए जाने पर सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण पर शुल्क के भुगतान से निर्माता को

कोई छूट नहीं है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 ए की उप-धारा 1 के तहत जारी सामान्य छूट संख्या 66 के तहत केंद्र सरकार ने उक्त छूट आदेश से जुड़ी तालिका के (3) में निर्दिष्ट विवरण के उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को छूट दी है।

11. जहां तक सल्फ्यूरिक एसिड का संबंध है, जिसका उपयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, शून्य शुल्क प्रदान किया जाता है। हालाँकि, तालिका इंगित करती है कि यह शर्त संख्या 5 के अधीन है। शर्त संख्या 5 का उल्लेख सामान्य छूट संख्या 66 से जुड़े अनुबंध में किया गया है जो इस प्रकार है: -

5. जहां इस तरह का उपयोग उत्पादन के कारखाने के अलावा कहीं और होता है, वहां छूट की अनुमति दी जाएगी यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल को हटाना) नियम, 2001 में निर्धारित प्रक्रिया की अनुमति है।

12. अपीलकर्ता का तर्क है कि उर्वरक संयंत्रों को उप-उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड की निकासी पर अधिसूचना संख्या के अनुसार शुल्क की दर शून्य है। 6/2002-सीई, हालांकि उर्वरक संयंत्रों द्वारा पोस्ट किए गए बांड के आधार पर, लेकिन फिर भी, माल को कुल छूट या शुल्क की शून्य दर के तहत मंजूरी दे दी जाती है और इसलिए 57 सीसी आकर्षित होता है। उनका तर्क है कि नियम 57 डी का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

13. चूंकि उत्तर इस प्रश्न पर निर्भर करता है कि क्या नियम 57 सीसी लागू होता है या नियम 57 डी लागू होता है, साथ ही इन नियमों की सही व्याख्या पर, हम इस समय इन नियमों को पुनः प्रस्तुत करते हैं: -

नियम 57 सीसी -

“छूट वाले अंतिम उत्पादों में उपयोग किए गए इनपुट पर क्रेडिट का समायोजन या निर्माता द्वारा अलग-अलग इन्वेंट्री और इनपुट के खातों का रखरखाव, (1) जहां एक निर्माता किसी भी अंतिम उत्पाद के निर्माण में लगा हुआ है जो शुल्क के साथ-साथ किसी अन्य में भी प्रभार्य है। अंतिम उत्पाद जो उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से मुक्त है या शुल्क की शून्य दर के लिए प्रभार्य है और निर्माता किसी भी इनपुट (ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले इनपुट के अलावा) पर निर्दिष्ट शुल्क का क्रेडिट लेता है जिसका उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है अंतिम उत्पादों की उपरोक्त दोनों श्रेणियों के निर्माण में या उसके संबंध में, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और चाहे उक्त अंतिम उत्पादों में शामिल हो या नहीं, निर्माता, जब तक कि उप-नियम (9) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है, भुगतान करेगा अंतिम उत्पादों की दूसरी

श्रेणी की कीमत के 8% के बराबर राशि (बिक्री कर और अन्य करों को छोड़कर, यदि कोई हो, ऐसे माल पर देय) ऐसे माल की बिक्री के लिए निर्माता द्वारा उनकी निकासी के समय लिया जाता है। कारखाना।

उप-नियम (1) में उल्लिखित राशि का भुगतान निर्माताओं द्वारा नियम 57 जी के उप-नियम (7) के तहत बनाए गए क्रेडिट खाते में या नियम 9 या उप-नियम 173 जी के तहत बनाए गए खातों में समायोजन द्वारा किया जाएगा और यदि ऐसा समायोजन है किसी भी कारण से संभव नहीं है, नियम 57 ए के तहत क्रेडिट का लाभ उठाने वाले निर्माता द्वारा राशि का भुगतान नकद में किया जाएगा।

उप-नियम (1) के प्रावधान केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले अंतिम उत्पादों पर लागू नहीं होंगे।

(4) उपनियम (1) के प्रावधान इन पर भी लागू नहीं होंगे-

(ए) अध्याय 39 के अंतर्गत आने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं;



(बी) अध्याय 40 के अंतर्गत आने वाले जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों या ठेलों और उनकी ट्यूबों पर उपयोग किए जाने वाले प्रकार के टायर;

(सी) काले और सफेद टेलीविजन सेट, अध्याय 85 के अंतर्गत आते हैं

(डी) समाचार प्रिंट, रूल या शीट में, अध्याय शीर्षक संख्या 48.01 के अंतर्गत आते हैं; जो उस पर लगने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क या शून्य दर शुल्क से मुक्त हैं।

(5) उप नियम (3) या उप-नियम (4) में निर्दिष्ट और उप-नियम (1) के प्रावधानों से बाहर किए गए अंतिम उत्पादों के मामले में, निर्माता शुल्क के क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा कारखाने से उनकी निकासी के समय ऐसे अंतिम उत्पादों में निहित इनपुट के लिए। उप-नियम (1) के प्रावधान उन अंतिम उत्पादों पर भी लागू नहीं होंगे जो नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार बांड के तहत निर्यात किए जाते हैं।

उप-नियम (1) के प्रावधान तब भी लागू होंगे, भले ही जिन इनपुट पर क्रेडिट लिया गया है, वे वास्तव में उपयोग

नहीं किए गए हैं या अंतिम उत्पादों की किसी विशेष निकासी में शामिल नहीं हैं।

यदि कोई सामान निर्माता द्वारा फैक्ट्री गेट पर नहीं बेचा जाता है, बल्कि डिपो से या कंसाइनमेंट एजेंट के परिसर से या किसी अन्य परिसर से बेचा जाता है, तो कीमत (बिक्री कर और अन्य करों को छोड़कर, यदि कोई हो, देय) जिस पर ऐसे सामान आमतौर पर ऐसे डिपो से या कंसाइनमेंट एजेंट के परिसर से या किसी अन्य परिसर से विनिर्माता द्वारा बेचे जाते हैं, उन्हें उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए कीमत माना जाएगा।

किसी भी सामान के निर्माता में या उसके संबंध में उपयोग किए जाने वाले इनपुट (फ्लू के रूप में उपयोग किए जाने वाले इनपुट के अलावा) के संबंध में, जो उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं या शुल्क की शून्य दर से प्रभार्य हैं, निर्माता को उपरोक्त उद्देश्य के लिए इनपुट की प्राप्ति और उपयोग की अलग-अलग सूची और खाते बनाए रखें और ऐसे इनपुट पर भुगतान किए गए निर्दिष्ट शुल्क का क्रेडिट नहीं लेंगे।"

नियम 57 डी -

“कुछ परिस्थितियों में शुल्क के क्रेडिट से इनकार नहीं किया जाएगा या उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा-(1) निर्दिष्ट शुल्क के क्रेडिट से इस आधार पर इनकार या बदलाव नहीं किया जाएगा कि इनपुट का हिस्सा निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी अपशिष्ट, कचरा या उप-उत्पाद में निहित है। अंतिम उत्पाद का, या कि अंतिम उत्पाद के निर्माण के दौरान इनपुट बेकार हो गए हैं, चाहे ऐसा अपशिष्ट या कचरा या उप-उत्पाद उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से मुक्त हो या शून्य दर पर प्रभार्य हो। शुल्क का या नियम 57 ए के तहत अंतिम उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट नहीं है।”

14. विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री परासरन ने रिट याचिकाओं पर विचार करने में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं क्योंकि उनके अनुसार, अभी तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस संबंध में उनका तर्क यह था कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उक्त कारण बताओ नोटिस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। हालाँकि, कारण बताने के बजाय, कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिकाएँ दायर की गईं, जिसे समय से पहले खारिज कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया है कि उच्च

न्यायालय को, सामान्य रूप से, कारण बताओ नोटिस की वैधता पर सवाल उठाने वाली रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए।

15. गुण-दोष के आधार पर, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा मॉडवेट नियमों के नियम 57 सीसी और सीENVAT नियमों के नियम 6 की क्रमशः दी गई व्याख्या सही नहीं थी। जब इन नियमों की भाषा स्पष्ट और सुस्पष्ट हो तो उच्च न्यायालय को व्याख्या का शाब्दिक नियम लागू करना आवश्यक था।

16. इससे पहले कि हम उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या पर ध्यान दें और भारत संघ के इस तर्क पर चर्चा करें कि क्या नियम 57 सीसी की शाब्दिक व्याख्या की जानी है, सल्फ्यूरिक एसिड के गुणों को समझना आवश्यक होगा। जिंक के उत्पादन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के उपयोग सहित ऊपर जो समझाया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड वास्तव में एक उप-उत्पाद है। वास्तव में, उत्तरदाताओं द्वारा अपनी बैलेंस शीट के साथ-साथ विभिन्न अन्य दस्तावेजों में भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है, जो उत्तरदाताओं द्वारा नीचे की अदालतों में दायर किए गए थे। यह भी पार्टियों का एक सामान्य मामला है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और बिड़ला कॉपर की स्थापना क्रमशः जस्ता और तांबे का उत्पादन करने के लिए की गई थी, न कि सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था,

जिसे विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा विवादित नहीं किया जा सकता था, कि केंद्रित अयस्क की कैल्सीनेशन प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड का उद्भव एक तकनीकी आवश्यकता है और फिर गैर के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड में इसका रूपांतरण होता है। -प्रदूषणकारी उपाय सल्फ्यूरिक एसिड को अंतिम उत्पाद की स्थिति तक नहीं बढ़ा सकते। तकनीकी रूप से, व्यावसायिक रूप से और आम बोलचाल में, सल्फ्यूरिक एसिड को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर की कंपनियों द्वारा अलौह धातुओं के निष्कर्षण में एक उप-उत्पाद के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि विभाग ने ट्रिब्यूनल के समक्ष यह स्थिति स्वीकार कर ली कि सल्फ्यूरिक एसिड एक उप-उत्पाद है।

17. इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता द्वारा अब ली गई स्थिति कि सल्फ्यूरिक एसिड को उप-उत्पाद के रूप में नहीं माना जा सकता है, को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एसके बागरिया ने विनिर्माण प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए यह भी बताया कि अयस्क सांद्रण (जस्ता या तांबा) का उपयोग पूरी तरह से जस्ता और तांबे के उत्पादन के लिए किया जाता है और धातु, जस्ता का कोई हिस्सा नहीं होता है। या तांबा सल्फ्यूरिक एसिड का हिस्सा बनता है जिसे साफ़ कर दिया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अयस्क सांद्रण से जस्ता के निष्कर्षण के परिणामस्वरूप तकनीकी आवश्यकता के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का उद्भव अनिवार्य रूप से

होगा। ऐसा नहीं है कि उत्तरदाता केवल धातु का उत्पादन करने के लिए जिंक सांद्रता की कम मात्रा का उपयोग कर सकते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जिंक सांद्रण की एक निश्चित मात्रा के परिणामस्वरूप रासायनिक सूत्र के अनुसार जिंक सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड का उद्भव होगा, जिस पर उत्तरदाताओं का कोई नियंत्रण नहीं है।

18. इन तथ्यों पर यह अदालत उत्तरदाताओं के संस्करण को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है कि अयस्क सांद्रण पूरी तरह से जस्ता के निष्कर्षण में खपत होता है और धातु का कोई भी हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड का हिस्सा नहीं बन रहा है।

19. एक बार जब हम अभिलेखों पर उपलब्ध उपरोक्त तथ्यात्मक, तकनीकी और वाणिज्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यह स्वीकार करना होगा कि उत्तरदाताओं ने जस्ता के उत्पादन में जस्ता सांद्रता की पूरी मात्रा का उपभोग किया है।

20. आइए अब हम उपरोक्त स्थिति की कसौटी पर नियम 57 सीसी में निहित स्थिति की जांच करें। इसमें कोई संदेह नहीं है, नियम 57 सीसी के अनुसार एक निर्धारिती को उन इनपुट के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो दो या दो से अधिक अंतिम उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं जिनमें से एक शुल्क योग्य है

और दूसरा गैर-शुल्क योग्य है। उस स्थिति में, नियम 57 सीसी लागू होगा। उदाहरण के लिए, एक टायर निर्माता विभिन्न प्रकार के टायरों का निर्माण करता है, जिनमें से एक या अधिक को छूट दी गई थी जैसे पशु गाड़ियों और साइकिल टायरों में इस्तेमाल होने वाले टायर, जहां कार टायर और ट्रक टायर पर उत्पाद शुल्क लगता है। रबर, एक्सेलेरेटर, रिटार्डर, फिलर्स, सल्फर, वल्केनाइजिंग एजेंट जो टायर के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं, वास्तव में शुल्क योग्य और छूट वाले टायर दोनों के लिए सामान्य हैं। ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं को छूट वाले टायरों पर 8% की शुल्क मांग से बचने के लिए अलग रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य है। लेकिन जब हम पाते हैं कि उत्तरदाताओं के मामले में, ऐसा नहीं है कि जिंक अयस्क सांद्रण की कुछ मात्रा सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में चली गई है, तो नियम 57 सीसी की प्रयोज्यता को आकर्षित किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिंक की पूरी मात्रा वास्तव में जिंक के उत्पादन में उपयोग की गई है और सल्फ्यूरिक एसिड में इसका कोई हिस्सा नहीं पाया जा सकता है। यही कारण है कि, उत्तरदाताओं ने जिंक के उत्पादन के लिए जिंक सांद्रण की सूची बनाए रखी और हम उत्तरदाताओं के इस कथन से सहमत हैं कि उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले जिंक सांद्रण के लिए अलग रिकॉर्ड बनाए रखना कोई आवश्यकता नहीं थी और वास्तव में यह असंभव है। सल्फ्यूरिक एसिड का. इसलिए, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि जिस तरह से प्रतिवादी रिकॉर्ड और इन्वेंट्री बनाए रख रहा था, उसमें

57 सीसी की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया गया था और छूट वाले सल्फ्यूरिक एसिड पर नियम 57 सीसी के तहत 8% की वसूली की शरारत आकर्षित नहीं होती है।

21. जैसा कि पहले ही बताया गया है, विद्वान सॉलिसिटर जनरल का तर्क यह था कि मॉडवैट/सेनवैट नियमों के नियम 57 सीसी और नियम 6 में क्रमशः व्याख्या के शाब्दिक नियम की आवश्यकता होती है, जिसे लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी भाषा इस संबंध में स्पष्ट थी। हम यह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, नियम 57 सीसी या नियम 6 के प्रावधान दो अंतिम उत्पादों में इनपुट के सामान्य उपयोग की परिकल्पना करते हैं यानी एक शुल्क योग्य और दूसरा उसी की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त। उन्होंने कहा कि जब आम इनपुट के उपयोग से दो अंतिम उत्पाद सामने आते हैं, एक उत्पाद शुल्क योग्य और दूसरा छूट वाला, तो प्रावधान लागू होंगे। छूट प्राप्त उत्पाद का निर्माण करने के करदाता के इरादे का प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। यह इरादा या अनजाने में हो सकता है लेकिन यदि विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान जो परिणाम होता है वह उक्त प्रावधानों के अर्थ के अंतर्गत आने वाला "अंतिम उत्पाद" है, तो प्रावधान संबंधित परिणामों के साथ पूर्ण रूप से लागू होंगे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नियम 57D में "उपोत्पाद" के साथ-साथ 'अपशिष्ट और कचरा' शब्दों का उपयोग किया गया है। 'उप-उत्पाद' शब्द को अनिवार्य रूप से अपना रंग और अर्थ इसके साथ आने वाले शब्दों "बर्बाद और इंकार" से



लेना होगा। किसी भी स्थिति में "उप-उत्पाद" का अर्थ "अंतिम उत्पाद" नहीं हो सकता। इस नियम का मतलब केवल यह है कि मॉडवैट क्रेडिट को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि निर्माण के दौरान, गैर-उत्पाद शुल्क योग्य सामान भी उत्पन्न होते हैं।

22. इस तर्क को विस्तृत करते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि मॉडवैट और सेनवैट क्रेडिट के संदर्भ में "अंतिम उत्पाद" शब्द को मॉडवैट/सेनवैट नियमों में दिए गए अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। नियम 57ए में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि इस धारा के प्रावधान ऐसे अंतिम उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं (उस धारा में अंतिम उत्पाद के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे। पुनः, सेनवैट क्रेडिट नियम, 2002 का नियम 2(सी) "अंतिम उत्पादों" को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है माचिस को छोड़कर इनपुट से निर्मित या उत्पादित उत्पाद शुल्क योग्य सामान। सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 का नियम 2 (एच) "अंतिम उत्पादों" को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है इनपुट से निर्मित या निर्मित, या इनपुट सेवा में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद शुल्क योग्य सामान। इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधानों में संदर्भित अंतिम उत्पादों का मतलब केवल उत्पादित या निर्मित उत्पाद शुल्क योग्य सामान हो सकता है। मामलों के वर्तमान सेट में, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा फ्लेक्स, ट्राइक्लोरो एथिलीन और फॉस्फोरिल ए और फॉस्फोरिल बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम के विभिन्न शीर्षकों के तहत भारत में

निर्मित और उत्पादित उत्पाद शुल्क योग्य सामान हैं । दलील यह थी कि यदि ये उत्पाद छूट वाले हैं या शुल्क की शून्य दर के अधीन हैं, तो जिन इनपुट पर मॉडवेट/सेनवेट क्रेडिट का दावा किया गया है, उनका उपयोग उपरोक्त अंतिम उत्पादों के निर्माण में किया जाएगा, उन पर मॉडवेट के नियम 57 सीसी/नियम 6 की कठोरता लागू होगी। / सेनवेट क्रेडिट नियम।

23. इसी दिशा में, उनका आगे का निवेदन यह था कि शब्द "द्वारा-उत्पाद" को न तो अधिनियम में और न ही नियमों में परिभाषित किया गया है। इस मामले में शब्दकोश के अर्थों का सहारा नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि अंतिम उत्पादों को उप-उत्पादों के रूप में माना जाएगा जो नियम 57 सीसी और नियम 6 की स्पष्ट भाषा को पराजित करेगा जो अंतिम उत्पादों पर लागू होते हैं। एकमात्र परीक्षण "विनिर्मित या उत्पादित माल की उत्पाद शुल्क योग्यता" है और केवल अगर इस परीक्षण की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो सामान 'अंतिम उत्पाद' हो सकता है और कभी भी 'उप-उत्पाद' नहीं हो सकता है। इस आधार पर, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि बिड़ला कॉपर मामले में ट्रिब्यूनल के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति पर भी कि माल 'उप-उत्पाद' है, प्रतिवादी द्वारा भरोसा नहीं किया जा सकता है।

24. यह अनुरोध करते हुए कि इन नियमों की उपरोक्त व्याख्या इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाए, श्री परासरन का कहना था कि ऐसी स्थिति में स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड बनाम सीसीई के मामले में निर्णय ; 1989 (44) ईएलटी 794 लागू नहीं था, न ही सीसीई बनाम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निर्णय लागू था ; 2008 (232) ईएलटी 7 प्रतिवादी द्वारा पर भरोसा किया गया। इसी तरह उनका कहना था कि रैलिस इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला; 2009 (233) ईएलटी 301 गलत था जिसमें लिया गया दृष्टिकोण उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के विपरीत है।

25. ये तर्क आकर्षक लग सकते हैं. हालाँकि, इसमें शामिल प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, जो पहले ही ऊपर बताई गई है और हमारे द्वारा बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम इन प्रस्तुतियों से सहमत होने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं कि बिड़ला कॉपर (2011 का सीए नंबर 2337) के मामले में ट्रिब्यूनल ने स्वदेशी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में फैसले के बाद मामले का फैसला किया है। उस मामले में, पॉलिएस्टर और इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल को डीएमटी के साथ प्रतिक्रिया दी गई थी। मेथनॉल उत्पाद शुल्क योग्य नहीं था जबकि पॉलिएस्टर फाइबर उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी था। पॉलिएस्टर पर शुल्क के भुगतान के लिए एथिलीन ग्लाइकोल पर भुगतान किए गए शुल्क का पूरा श्रेय लिया गया।

विभाग ने एक स्थिति ली कि एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग मेथनॉल के उत्पादन में किया गया था और एथिलीन ग्लाइकोल पर लिए गए आनुपातिक क्रेडिट को उलट दिया जाना था। इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मेथनॉल का उद्भव एक तकनीकी आवश्यकता थी और यह नहीं कहा जा सकता कि एथिलीन ग्लाइकोल का कोई भी हिस्सा मेथनॉल के उत्पादन में उपयोग किया गया था और वास्तव में यह माना गया था कि एथिलीन ग्लाइकोल की कुल मात्रा का उपयोग पॉलिएस्टर के उत्पादन के लिए किया गया था। इन तीनों अपीलों के तथ्य स्वदेशी पॉलीटेक्स (सुप्रा) में निर्धारित तथ्यों और कानून के समान प्रतीत होते हैं। इसलिए, यह निर्णय बिल्कुल लागू है।

26. इसके अलावा, नियम 57 सीसी के प्रावधानों को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इस नियम में निहित मोडवैट क्रेडिट की योजना को समझने के लिए, नियम 57 ए, 57 बी और 57 डी के साथ-साथ नियम 57 सीसी को एक साथ पढ़ना अपरिहार्य हो जाता है। हमने पहले ही ऊपर नियम 57 डी पुनः प्रस्तुत कर दिया है। उपरोक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह आसानी से समझा जा सकता है कि इस्तेमाल किए गए शब्द 'इनपुट', 'अंतिम उत्पाद', 'उप-उत्पाद', 'अपशिष्ट उत्पाद' आदि हैं। हमारा मानना है कि इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। व्यापार में व्यावसायिक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए। उस संदर्भ में जब हम नियम 57 सीसी के माध्यम से स्कैन करते हैं, तो समान सामान्य इनपुट

के साथ निर्मित अंतिम उत्पाद का संदर्भ समझ में आता है। इस नियम में अंतिम उत्पाद और उप-उत्पाद के उद्भव के बारे में बात नहीं की गई और फिर भी कहा गया कि नियम 57 सीसी लागू होगा। अपीलकर्ता नियम 57 सीसी को लागू करना चाहता है जबकि नियम 57 डी अंतिम उत्पाद और उप-उत्पाद पर नियम 57 सीसी के आवेदन के बारे में बात नहीं करता है जब उप-उत्पाद एक तकनीकी आवश्यकता के रूप में उभरा। अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार करना उप-उत्पाद और अंतिम उत्पाद को बराबर करने जैसा होगा, जिससे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होने के बावजूद अंतर खत्म हो जाएगा। गौरतलब है कि स्टरलाइट (सुप्रा) में ट्रिब्यूनल की इस व्याख्या के खिलाफ विभाग द्वारा अपील नहीं की गई थी।

27. हम विद्वान महासचिव के इस कथन से भी सहमत होने में असमर्थ हैं कि गेल के मामले में निर्णय लागू नहीं है। गौरतलब है कि उस मामले में यह सवाल चर्चा में आया था कि क्या नियम 57 सीसी तब लागू होगा जब शुल्क के भुगतान के बिना उप-उत्पादों को मंजूरी दे दी जाएगी। यह माना गया कि जब तक लीन गैस एक उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त की जाती है, न कि अंतिम उत्पाद के रूप में, नियम 57 सीसी लागू नहीं होगा। इसलिए, हमारा विचार है कि प्रतिवादी का मामला पूरी तरह से गेल के मामले के फैसले से कवर होता है।

28. इस स्तर पर हमें उच्च न्यायालय के समक्ष हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका की गैर-धारणीयता के तर्क से निपटना चाहिए। निस्संदेह, इसने कारण बताओ स्तर पर रिट याचिका दायर की थी। हालाँकि, यह केवल कारण बताओ नोटिस की वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया था। रिट याचिका में नियम 57 सीसी की वैधता को भी चुनौती दी गई थी। यही एक कारण था जिसके कारण रिट याचिकाओं पर विचार किया गया, और यह सही भी है, यह अलग बात है कि नियम की व्याख्या करते समय, उच्च न्यायालय ने उक्त नियम को पढ़ने और एक व्याख्या देने का फैसला किया जो इसे बुराई से बचाएगा। असंवैधानिकता का. इसके अलावा, विभाग द्वारा दायर की गई अन्य वैधानिक अपील सीईएसटीएटी के आदेश के खिलाफ है, जिसमें समान प्रश्न शामिल हैं। हमारे समक्ष अपील में भी मामले पर विस्तार से बहस की गई है और हम गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय ले रहे हैं। इन सभी कारणों से वैकल्पिक उपचार के तर्क को खारिज करना होगा।

29. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे लागत सहित खारिज कर देते हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती शैली परवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।